विचार-प्रवाह... ट्रंप भी बैकफुट पर

पेज थ्री

देहरादून, मंगलवार, 14 जनवरी 2020

PAGE 3 PUBLICATION

मौसम अधिकतम 18.0° न्यूनतम 9.0°

41859.69

2 श्रृंगला ने डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात

7 मैं बल्लेबाजी क्रम में नीचे आ सकता हूं

बिहार में एनआरसी नहीं

सीएए पर संसद में चर्चा होः नीतीश कुमार

विरोध

- विपक्ष ने पटना में विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया
- एनआरसी का मुद्दा सिर्फ असम के परिप्रेक्ष्य में है और इसे पीएम मोदी भी स्पष्ट कर चुके हैं

नीतीश की सफाई

नीतीश कुमार पहले भी दावा करते रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। एक बार फिर सोमवार को उन्होंने विधानसभा में यह दावा दोहराया। सीएम ने कहा, 'बिहार में एनआरसी का कोई सवाल ही नहीं है। यह मुद्दा सिर्फ असम से जुड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बारे में स्पष्ट कर चुके हैं।

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

पटना। नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने दो टूक कहा कि सीएए पर बहस होनी चाहिए और अगर सभी पक्ष सहमत होते हैं तो फिर इस पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार ने साफ किया कि बिहार में एनआरसी लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। सोमवार को विधानसभा विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दावा किया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। नीतीश ने कहा कि एनआरसी का मुद्दा सिर्फ असम के परिप्रेक्ष्य में है और इसे पीएम नरेंद्र मोदी भी स्पष्ट कर चुके हैं। बता दें कि नागरिकता कानून के खिलाफ जेडीयू में ही दो फाड़ की स्थिति तब बन गई जब पार्टी लाइन से इतर उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बयान दिया। प्रशांत किशोर ने रविवार को भी सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ की। इसके बाद से कई तरह की सियासी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। फिर भी नहीं की गई कार्रवाई प्रशांत किशोर नीतीश को भी जेडीयू की धर्मनिरपेक्ष छवि की याद दिलाते रहे हैं। पीके के अलावा पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलयावी ने भी सीएए का समर्थन करने को लेकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयान दे चुके हैं। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की।

साजिश के तहत शांत रहे नीतीश कुमार

दरअसल, प्रशांत किशोर की तरफ से लगातार सीएए के विरोध के बीच लंबे समय तक नीतीश कुमार एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर खामोश रहे। बिहार की सियासत में अब कहा जाने लगा है कि पीके नीतीश की मजबूरी हैं क्योंकि उन्हीं के जरिए नीतीश कई रणनीति पर काम कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोची-समझी रणनीति के तहत इस मुद्दे पर अधिकतर खामोश रहे हैं।

यूपी में कमिश्नरेट सिस्टम को मंजूरी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था के लिहाज से एक अहम फैसला लिया है। अब राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। लखनऊ में सुजीत पांडेय की कमिश्नर पद पर तैनाती की गई है। वहीं, आलोक सिंह नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं।

बता दें कि 15 राज्यों के 71 शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली पहले से लागू है। यूपी में सीएम योगी के सत्ता संभालने के बाद इस सिस्टम के लिए कवायद शुरू तो हुई थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के दबाव में बात अंजाम तक नहीं पहुंच पाई थी।

मोदी, शाह कर रहे हैं गुमराह

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

- सीएए प्रोटेस्ट पर विपक्ष की बैठक के बाद सोनिया का केंद्र पर हमला

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा के लिए बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों पर अत्याचार कर रही है और घृणा फैला रही है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और संविधान को ताक पर रखकर उथल-पुथल की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए झटके की बात रही कि मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी शिवसेना ने भी इस बैठक से किनारा कर लिया।

सरकार ने लोगों पर निकाला गुस्साः बैठक के बाद सोनिया गांधी ने दावा किया देशभर में लोगों ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, इन प्रदर्शनों के बाद सरकार का गुस्सा फूट पड़ा और वह अब खुलकर सामने आ गया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्रवाई बहुत ही अजीब है।

सोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोगों को बरगलाने का काम किया है।

अपनी बात से मुकर गए मोदीः सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह अपनी ही बात से मुकर गए हैं। जेएनयू, बीएचयू और जामिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने उनका आतंक देखा है। मोदी-शाह की सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। इस बैठक में कांग्रेस के 19 नेताओं के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार, लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी, डी राजा, जीएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदि शामिल हुए।

आश्वासन को भी नहीं माने जामिया स्टूडेंट

धरना

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने तक परीक्षा में शामिल नहीं होने की जिद्द पर अड़ गए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर (वीसी) नजमा अख्तर के आश्वासनों को दरकिनार करते हुए आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है।

वीसी ने सुबह से ही बयान की मांग कर रहे छात्रों के बीच आकर कहा कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया कल (मंगलवार) से ही शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एफआईआर नहीं की जा रही है, इसलिए गारंटी नहीं दी जा सकती है कि उनकी प्रक्रिया पर पुलिस क्या ऐक्शन लेगी।

छात्रों का आक्रोश कम नहीं होता देख वीसी ने कहा कि परीक्षा की तारीखें नए सिरे से शेड्यूल की जाएंगी।

वीसी का आश्वासन

आक्रोशित छात्रों के हुजूम के बीच खड़ी वीसी को अपनी बात रखने में भी काफी मशक्कत हो रही थी। उन्होंने स्टूडेंट्स को समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन छात्र बीच-बीच में हंगामा करते दिखे और पुलिस पर एफआईआर किए जाने तक धरने पर बैठे रहने की जिद्द पर अड़ गए। वीसी ने छात्रों को बताया कि कैंपस में सुरक्षा इंतजामों को दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस बिन पूछे कैंपस में दाखिल हुई थी। छात्रों को पीटा गया। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

अब तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर

जामिया के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम ए. खान ने इसे लेकर क्राइम ब्रांच को लेटर लिखा है। उन्होंने डेप्युटी पुलिस कमिश्नर को लिखा है कि 15 दिसंबर को लाइब्रेरी में गलत तरीके से पुलिस के घुसने, स्टूडेंट्स को चोट और लाइब्रेरी को नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर अभी पेंडिंग है। जामिया नगर थाने और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में पुलिस की दर्ज एफआईआर क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो गई। ऐसे में पता चला है कि यह मामला भी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है।

कोर्ट ने पुलिस समेत, वॉट्सऐप, गूगल, ऐपल और पुलिस से मांग जवाब

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के साथ राज्य सरकार, वॉट्सऐप, गूगल और ऐपल से जेएनयू में 5 जनवरी को हुई हिंसा से संबंधित डेटा और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने पर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आगे की जांच के लिए यह जानकारी जरूरी है। जेएनयू के तीन प्रफेसरों ने इसके लिए याचिका दी थी। कोर्ट का कहना है कि हिंसा से संबंधित जानकारी भविष्य के लिए जरूरी है इसलिए इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया इस विषय में जेएनयू प्रशासन से बात की गई।

संक्षिप्त समाचार

हिम्मत हैं तो किसी यूनिवर्सिटी में बिना पुलिस के जाएं

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस नेतृत्व में विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं कि वह बिना पुलिस के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर दिखाएं। वह बताएं कि देश के लिए वह क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने जेएनयू और जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध को लेकर कहा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता।

आतंकियों के साथ डीएसपी की गिरफ्तारी के मामले की जांच करेगी एनआईए

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) श्रीनगर। शनिवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में दो आतंकियों के साथ गिरफ्तार डीएसपी से सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला किया है। कुलगाम में गिरफ्तार किए गए डीएसपी देविंदर सिंह के पास से दो एके-47 राइफलों समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। रविवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने रविवार को कहा कि डीएसपी की आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता एक जघन्य अपराध है।

सेना का जवान बर्फ में फिसलकर लापता

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग इलाके से लगने वाली एलओसी पर तैनात एक जवान के लापता होने की खबर है। बताया जा रहा है कि गढ़वाल राइफल्स के हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी बारामुला के गुलमर्ग में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। राजेंद्र सिंह नेगी गुलमर्ग में फॉरवर्ड इलाकों में पट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात थे। सूत्रों के कहना है कि लापता जवान की तलाश के लिए सेना की कई टीमों को फॉरवर्ड इलाकों में भेजा गया है।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact: **Gadoli Media Ventures**
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in